टिड्डियों को समाप्त किया जाना

1509. **श्री अजीत जोगी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ब्रिटेन और चीन की तर्ज पर टिड्डी समाप्ति योजना शुरू करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इस प्रयोजनार्थ कोई वित्तिय सहायता प्रदान की गई है, यदि हां, तो कितनी, और

(ग) सरकार द्वारा विश्व के अन्य विकसित देशों की भांति टिड्डी नियंत्रण हेतु प्रयोग की जा रही तकनीक का विकास करने के लिए क्या कदम उठाए गये है/उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) महोदय, सरकार अनुसूचित टिड्डी क्षेत्र के 2.0 लाख वर्ग कि. मी. से अधिक क्षेत्र में टिड्डी के सर्वेक्षण तथा नियंत्रण के लिए एक स्थायी टिड्डी चेतावनी संगठन चला रहा है । सरकार को चीन और यूनाइटेड किंगडम में विकसित पर्यावरणीय रूप से सही टिड्डी उन्मूलन की किसी भी योजना के बारे में जानकारी नहीं है । यूनाइटेड किंगडम में फफून्द रोग-जनकों के साथ टिड्डी के जैव-नियंत्रण के बारे में परीक्षण किए गए हैं । तथापि, इस पद्धति की व्यावसायिक व्यवहार्यता अभी स्थापित की जानी है । अब तक यह सम्भव नहीं हुआ है कि जैव-नियंत्रण एजेन्टों से टिड्डी प्लेग का नियंत्रण किया जा सके।

(ग) टिड्डी पर निगरानी रखने और पूर्व-सूचना देने में सुधार करने के लिए एक दूर संवेदी प्रयोगशाला की स्थापना करके टिड्डी नियंत्रण प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने हेतु, सरकार द्वारा प्रयास किए गए हैं ।

मध्य प्रदेश में कपास का उत्पादन

1510. **श्री अजीत जोगी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में कपास को एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और रेशेदार फसल के रूप में उगाया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1994 के अन्त तक राज्य में कुल कितने क्षेत्र में कपास की खेती होती थी और वर्ष 1993-94 के दौरान कपास का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ग) क्या वर्ष 1993-94 के दौरान मध्य प्रदेश में कपास का उत्पादन गत वर्ष की तुलना में बहुत कम हुआ है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण है ; और

(ङ) वर्ष 1994-95 के दौरान कपास उत्पादन के क्षेत्र में कितनी वृद्धि होने की संभावना है और वर्ष 1994-95 के दौरान कपास का अनुमानत : कितना उत्पादन होने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान मध्य प्रदेश में कपास क्षेत्र तथा उत्पादन क्रमशः 477 हजार हैक्टेयर तथा प्रत्येक 170 किलोग्राम की गांठ की 406 हजार गांठ था ।

(ग) जी नहीं

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ङ) वर्ष 1994-95 के दौरान मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 2 प्रतिशत अधिक होने की संभावना है जबकि चालू वर्ष में कपास के अन्तर्गत क्षेत्र में किसी प्रकार के महत्वपूर्ण परिवर्तन की आशा नहीं है ।

गुजरात द्वारा बाढ़ राहत हेतु मांगी गई सहायता

1511. **श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित हुए किसानों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मांगी गई सहायता अब प्रदान कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सहायता राशि अपर्याप्त होने के कारण धनराशि जारी करने/भुगतान करने संबंधी मानदंडों में संशोधन करने हेतु कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ.) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) तथा (ख) गुजरात सरकार ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें हाल की बात से प्रभावित क्षणों में राहत कार्यों के लिए 648.00 करोड़ रुपये की वित्तीय आवश्यकता को दर्शाया गया है। इसमें प्रभावित किसानों की सहायता के लिए 82.75 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है। राहत व्यय वित्तपोषण की मौजूदा स्कीम के आधार पर, आपदा राहत निधि में वर्ष 1994-95 के लिए सम्पूर्ण केन्द्रीय अंश की 63.75 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार को दे दी गई है।

(ग) से (ङ) दसवें वित्त आयोग ने भी राहत व्यय वित्त पोषण की मौजूदा स्कीम की समीक्षा की है। राज्य सरकार ने इस मामले पर अपना ज्ञापन सीधे आयोग को प्रस्तुत किया था।

Agricultural Costs and Prices Commission

1512. SHRI BHUPINDER SINGH MANN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the terms of reference of the Agricultural Cost and Prices Commission (ACPC);

(b) whether Government consider to amend the terms of reference of the commission to match the liberalization policies of Government ;

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ;

(d) whether Government would make public the details of calculations of minimum support price of agricultural produce: and

(e) if so, by when and if not, the reason therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA RAO) : (a) The terms of reference of the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) are given in the enclosed Statement (*See* below)

(b) and (c) While formulating its recommendations on Price Policy the CACP apart from making a comprehensive overview of the the entire structure of the economy of a particular commodity considers a number of important factors i.e., cost of production, changes in input prices, input/output price parity, trends in market prices, demand and supply situation, inter-crop price parity, effect on industrial costs structure, effect of general price level, effect on cost of living, international market price situation and parity between prices paid and prices received by farmers. Thus, the current policies of the Government including those of liberalization are kept in view.

(d) and (e) The Reports of the CACP containing all relevant data are made public.

Statement

The terms of reference of the Commission for Agricultural Costs and Prices are as under :—

1. To advise on the price policy of paddy, rice wheat, jowar, bajra, maize, ragi, barley, gram, tur, moong, urad, sugarcane, groundnut, soyabean, sunflowerseed, rapeseed and mustard, cotton, jute, tobacco and such other commodities as the Government may indicate from time to time with a view to evolving a balanced and integrated price structure in the perspective of the overall needs of the economy and with due regard to the interests of the producer and the consumer.

2. While recommending the price policy and relative price structure, the commission may keep in view the following :

(i) The need to provide incentive to the producer for adopting improved technology and for developing a production pattern broadly in the light of national requirements.

(ii) The need to ensure rational utilisation of land, water and other production resources,